

स्वतंत्रता के बाद शिक्षा

Dr. Mukesh Pancholi

आचार्य राममूर्ति समिति, 1990 –

1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई, 1987 से इसका क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया। परंतु 3 वर्ष बाद मई, 1990 में इस नीति की समीक्षा के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। “प्रबुद्ध व मानवीय समाज की ओर” शीर्षक से 26 दिसम्बर, 1990 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

इस समिति की रिपोर्ट के प्रारंभ में यह स्वीकार किया गया कि 1986 के बाद देश में मूल्यों में ह्रास, वर्ग भेद, धार्मिक उन्माद बढ़ा है। इसके बाद NPE 1986 के कार्यान्वयन की समीक्षा प्रस्तुत की और निम्न सुझाव दिए-

शिक्षा की संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986-92

पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधी समीक्षा व सुझाव –

समिति ने देखा कि NPE, 1986 के तहत शिशुओं की देखभाल व शिक्षा के लिए गति मंद है, उस समिति ने सुझाव दिया कि शिशुओं की देखभाल व शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी का विस्तार किया जाए व कार्यों को उन्नत किया जाए।

प्राथमिक शिक्षा –

समिति ने स्पष्ट किया कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के कार्य को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्ष 1990-91 तक 50% विद्यालयों को Operation Black Board योजना का लाभ पहुंचाया जाना था, परन्तु अब तक केवल 30% प्राथमिक विद्यालयों को ही इसका लाभ मिला है। इन 30% में जो भवन बनाए गए हैं, वे अच्छे नहीं हैं।

उन्होंने सुझाव दिया कि प्राथमिक स्तर पर शत-प्रतिशत नामांकन, शत-प्रतिशत उपस्थिति व शत-प्रतिशत सफलता के लिए ब्लैकबोर्ड योजना का क्रियान्वयन उचित ढंग व सही गति से किया जाए व प्राथमिक शिक्षा को मूल्यपरक शिक्षा बनाया जाए।

माध्यमिक शिक्षा संबंधी समीक्षा व सुझाव –

NPE 1986 के अनुसार पूरे देश में 10 + 2 + 3 शिक्षा संरचना लागू होनी थी, जो अभी तक हो नहीं पाई थी, देश में 261 नवोदय विद्यालय खोले गए थे, जिनका भी कोई लाभ नहीं हुआ था, + 2 पर 1995 तक 25% छात्र-छात्राओं को व्यावसायिक धारा में लाने का लक्ष्य है परन्तु अभी (1990) तक केवल 2.5% छात्रों को इस धारा में लाया गया था, इस संदर्भ में समिति ने पहला सुझाव यह दिया कि इस स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ईमानदारी से क्रियान्वयन किया जाए व दूसरा सुझाव दिया कि सार्वजनिक स्कूल प्रणाली को ईमानदारी से लागू किया जाए, व शिक्षा मूल्यपरक होनी चाहिए।

उच्च शिक्षा संबंधी समीक्षा व सुझाव –

NPE, 1986 में उच्च शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने हेतु विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात कही गई थी और 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। उच्च शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए प्रवेश पर नियंत्रण की बात कही गई थी, वह नहीं किया गया। शिक्षकों के कार्यों का मूल्यांकन भी औपचारिकता तक सीमित रहा। ना ही उच्च शिक्षा संस्थानों को अधिक आर्थिक सहायता देने के वादे को पूरा किया गया।

सबसे अधिक चिंता का विषय यह था कि अबतक (1990) उच्च शिक्षा में अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व बना हुआ था।

समिति ने उच्च शिक्षा के स्तर को उन्नत बनाने के लिए विश्वविद्यालयों पर कठोर नियंत्रण व प्रवेश के लिए चयन प्रणाली के पालन का सुझाव दिया।

व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा संबंधी समीक्षा व सुझाव-
NPE, 1986 में कम्प्यूटर शिक्षा पर बल दिया गया, निम्न स्तर की तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को बंद करने की बात कही गई।

इस बीच कम्प्यूटर शिक्षा में तो काफी सुधार हुआ, परन्तु अन्य सबमें सुधार नहीं हुआ।

इस संदर्भ में समिति ने शिक्षा को रोजगार-परक बनाने व ऐसी उच्च शिक्षा तकनीकी संस्थानों को उन्नत बनाने की बात कही। उन्होंने सुझाव दिया अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) को संवैधानिक दर्जा दिया जाए व उसके क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए जाए।

प्रौढ़ शिक्षा संबंधी समीक्षा व सुझाव –

समिति ने प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित सुझाव दिया कि इस शिक्षा का उत्तरदायित्व मानव संसाधन मंत्रालय के शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय व श्रम मंत्रालय, तीनों के ऊपर होना चाहिए।

विशेष सुझाव –

1. पूर्व प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए परिवार कल्याण, पोषण व स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं में गति लाने व कार्यरत व्यक्तियों के कार्य क्षेत्र को विस्तृत करने का सुझाव दिया गया।
2. प्राथमिक शिक्षा के संबंध में अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा 14 वर्ष तक के बालकों के लिए सुझाव यह दिया कि 8वीं योजना के दौरान (1992-97) सभी बच्चों को 1 किमी. में प्राथमिक स्कूल उपलब्ध कराएं जाए। सभी बच्चों का नामांकन सुनिश्चित हो, अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रोग्राम उच्च प्राथमिक स्कूलों पर भी लागू प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात 2 : 1 लाने का सुझाव दिया।

3. माध्यमिक परीक्षा के लिए मा. शिक्षा परिषदों के पुनर्गठन व स्वायत्तशासी बनाने, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को लागू करने, कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था, नवोदय विद्यालय योजना को चालू रखने का सुझाव दिया।
4. उच्च शिक्षा के संबंध में समिति ने यूजीसी के क्षेत्रीय कार्यालय अतिशीघ्र स्थापित करने, पाठ्यक्रम विकास, उच्च शिक्षा के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 'एकेडमिक स्टॉफ कॉलेज योजना' का विस्तार व निम्न स्तर की उच्च शिक्षण संस्थाओं को बंद करने का सुझाव दिया।
5. प्रौढ़ शिक्षा के लिए नव-साक्षरों के लिए उत्तर साक्षरता कार्यक्रम व सतत् शिक्षा की व्यवस्था की जाए।

6. व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा के लिए AICTE की क्षेत्रीय समितियां गठित करने का सुझाव दिया।
7. शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रणाली में सुधार व प्रशिक्षण व्यवस्था जिला स्तर पर प्रशिक्षण संस्थानों (DIET) में की जाए।
8. केन्द्रीय भाषा संस्थान को स्वायत्तशासी निगम का दर्जा, ताकि भारतीय भाषाओं के विकास के लिए स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सकें।

माध्यमिक स्तर पर पूरे देश में त्रिभाषा सूत्र को समान रूप से लागू करने का सुझाव व उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं के प्रयोग को प्रोत्साहित किया गया।

9. जिला शिक्षा परिषदों की स्थापना जल्द से जल्द की जाए, वित्त के संबंध में राज्य प्राथमिक शिक्षा को प्रथम वरीयता दे व उच्च व तकनीकी शिक्षा को धीरे-धीरे स्ववित्तपोषित बनाए।

गणनाम समिति, 1993 –

वर्ष 1993 में गणनाम समिति का गठन किया गया, समिति ने निम्न सिफारिशें प्रस्तुत की -

- अकादमिक उत्कृष्टता को सुनिश्चित करने के लिए लचीलापन व स्वायत्तता दी जाए।
- डीम्ड विश्वविद्यालयों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित किया जाए।

- उच्चतर शिक्षा पर राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जाए।
- शिक्षा की गुणवत्ता को विनियमित किया जाए, और विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाए।

Dr. Mukesh Parichholi

महत्त्वपूर्ण प्रश्न

Dr. Mukesh Pancholi

1. "एक सजग / प्रबुद्ध व मानवतावादी समाज के लिए शिक्षा का उपयोग" विचार से संबंधित है -

(A) जी. राम. रेड्डी

(B) कोठारी आयोग

(C) मुदालियर आयोग

(D) आचार्य राममूर्ति समिति

Dr. Mukesh Pancholi

2. समेस्टर प्रणाली का सुझाव किसने दिया -

(A) कोठारी आयोग

(B) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968

(C) आचार्य राममूर्ति समिति

(D) राधाकृष्णन आयोग

Dr. Mukesh Pancholi

3. निम्न तथ्यों पर विचार करें व संगत को छांटिए (राममूर्ति समिति से) –

- I. देश के मूल्यों में ह्रास, वर्ग भेद, धार्मिक उन्माद बढ़ने के कारण, NPE 1986 की समीक्षा हेतु समिति गठित की गई।
- II. गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 26 दिसम्बर, 1990 में प्रस्तुत की, इस कमेटी के अध्यक्ष राममूर्ति थे।
- III. इस समिति का सुझाव था कि AICTE एक स्वायत्त संस्था के रूप में ही कार्य करें।
- IV. प्रौढ़ शिक्षा का उत्तरदायित्व केवल केन्द्र सरकार पर होना चाहिए।

(A) I, II, III

(B) II, III, IV

(C) II, IV

(D) I, II

4. उच्च शिक्षा के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए आचार्य राममूर्ति समिति द्वारा सुझाव दिया गया -

(A) जिला प्रशिक्षण संस्थानों में सामयिक आधार पर प्रशिक्षण

(B) 'एकेडमिक स्टॉफ कॉलेज योजना' का विस्तार

(C) प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विशेष संचालन योजना

(D) इनमें से कोई नहीं

Dr. Mukesh Pancholi

5. शैक्षिक नीति, 1986 में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के तहत Operation Black Board योजना के तहत 1990-91 तक 50% विद्यालयों को लाभ पहुंचाना था, परन्तु राममूर्ति समिति के अनुसार लाभान्वित विद्यालय थे -

(A) 75%

(B) 30%

(C) 45%

(D) 60%

6. आचार्य राममूर्ति समिति के अनुसार प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए -

(A) मूल्यपरक

(B) अक्षर ज्ञान आधारित

(C) व्यावहारिक

(D) आदर्शवादी

Dr. Mukesh Pancholi

7. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई -

(A) 1990

(B) 1992

(C) 1986

(D) 1985

Dr. Mukesh Pancholi

8. NPE से संबंधित सुझावों को छांटिए –

- I. कम्प्यूटर शिक्षा पर बल
- II. उच्च शिक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग
- III. उच्च शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना
- IV. शिक्षा के प्रबंध पर केन्द्रीकृत व संवैधानिक प्रावधान लागू करने का प्रस्ताव दिया।

(A) I, II, IV

(B) I, II, III

(C) II, III, IV

(D) I, III

9. शैक्षिक नीति, 1986 में विकलांग बालकों की शिक्षा व्यवस्था -

- (A) अलग से की गई
- (B) सामान्य बालकों के साथ
- (C) प्राथमिकता के आधार पर
- (D) उपरोक्त सभी

Dr. Mukesh Pancholi

10. शैक्षिक नीति, 1986 के लिए गठित समिति ने प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात सुझाया है -

(A) 2 : 1

(B) 1 : 1

(C) 1 : 2

(D) इनमें से कोई नहीं

Dr. Mukesh Pancholi

11. S → अकादमिक उत्कृष्टता के लिए शिक्षा तंत्र को स्वायत्त व लचीला बनाए जाने की अनुशंसा गणनाम समिति ने की।

R → उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग व गुणवत्ता के लिए अनुसंधान को प्रोत्साहन देना आवश्यक है।

(A) S व R किसी प्रकार से एक दूसरे संबंधित नहीं है।

(B) S गलत है, R सही है।

(C) R सही है, S गलत है।

(D) S व R दोनों सही, दोनों एक-दूसरे से संबंधित है।